भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3089

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

इंडिया एआई मिशन के तहत जीपीयू खरीद के लिए सतत रूप से पैनल बनाना

3089. श्री प्रताप चंद्र सारंगी:

डॉ. भोला सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत एआई मिशन के तहत ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) खरीद के लिए पैनल बनाने की सतत् प्रक्रिया के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एआई मॉडल विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग के साथ स्थापित साझेदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल के परिणामस्वरूप भारत की एआई कंप्यूटिंग क्षमता में अनुमानित वृद्धि क्या है; और

(घ) क्या जीपीयू दरों को समय-समय पर संशोधित करने का प्रावधान है और यदि हां, तो ऐसे संशोधनों की आवृत्ति कितनी है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन** को मंजूरी दे दी है, जो देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है।

इंडियाएआई मिशन में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, जिनमें इंडियाएआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई शामिल हैं। कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर , डेटा गुणवत्ता बढ़ाकर , घरेलू एआई विशेषज्ञता का पोषण कर, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित कर, उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देकर , स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन कर, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर और नैतिक पद्धतियों पर जोर देकर इस मिशन का उद्देश्य भारत के एआई परिदृश्य के भीतर जिम्मेदार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

इंडियाएआई मिशन के प्रमुख स्तंभों में से एक **इंडियाएआई कंप्यूट** है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की समर्पित एआई कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सेवा के रूप में कंप्यूट प्रदान करना है। इस इकोसिस्टम में 10,000 या अधिक जीपीयू का एआई कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है।

इस दिशा में, इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) ने 16 अगस्त, 2024 को जीपीयू सहित क्लाउड पर एआई सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक अनुरोध पत्र (आरएफई) प्रकाशित किया। 19 बोलीदाताओं ने अपनी एआई क्लाउड सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 10 बोलीदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है।

इंडियाएआई कंप्यूट पिलर में उल्लिखित 10,000 जीपीयू के लक्ष्य की तुलना में, सूचीबद्ध बोलीदाताओं ने **एल 1 दरों पर 14,517 जीपीयू** की पेशकश की है। इसके अलावा, क्लाउड पर सूचीबद्ध एआई सेवाओं तक पहुंचने और उनका लाभ उठाने के लिए एक इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल विकसित किया गया है, जो **औसतन 115 रुपये प्रति जीपीयू घंटे की दर से है, जिसमें सरकार 40% तक का समर्थन** प्रदान करती है।

प्रौद्योगिकियों और बाजार की कीमतों में बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए, इंडियाएआई एक **निरंतर इम्पैनलमेंट प्रक्रिया** को सक्षम बनाता है। इंडियाएआई किसी भी संशोधित दरों की खोज के लिए पैनलबद्ध एजेंसियों से नए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए हर तिमाही में पैनल को नवीनीकृत करेगा। पैनलबद्ध एजेंसियां एक संशोधित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी जो मौजूदा एल-1 दरों के समान या उससे कम हो सकता है। इंडियाएआई ने 21 फरवरी, 2025 को निरंतर पैनलबद्धिकरण के लिए आरएफई प्रकाशित किया है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है।

उद्योग सहयोग की दिशा में, इंडियाएआई ने एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मेटा,आईबीएम , माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ **समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर** किए हैं।

इंडियाएआई ने 30 जनवरी, 2025 को **भारतीय डेटासेट पर प्रशिक्षित अत्याधुनिक मूलभूत एआई मॉडल के निर्माण** में सहयोग करने के लिए स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए **प्रस्तावों के लिए एक कॉल** लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी एआई मॉडल स्थापित करना है जो भारतीय संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करते हुए और अवसरों का लाभ उठाते हुए वैश्विक मानकों के साथ संरेखित हो।

पहले महीने में, इंडियाएआई मिशन को **15 फरवरी तक कुल 67 प्रस्ताव** प्राप्त हुए हैं जिसका उद्देश्य भारत के फाउंडेशन मॉडल का निर्माण करना है, जिसमें स्थापित स्टार्टअप और शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की नई टीमों दोनों का योगदान है। फंडिंग सपोर्ट के साथ, इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाली टीमों द्वारा **जीपीयू की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुरोध** किया गया है।

*****